राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

वर्ष 14,अंक 353, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

कैंसर पीड़िता की मदद के लिए आगे आ रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता..03

जयकांत मिश्रा सदस्य पद के लिए हाई कोर्ट में फार्म भरते समय की शक्ति प्रदर्शन..04

नितिन गडकरी ने शिवराज चौहान के लिए बोली बड़ी बात, कहा- PM मोदी का सपना पूरा करने में शिवराज की भूमिका अहम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव मेला राजनीतिक, प्रशासनिक और कृषि जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी के कारण खासा चर्चित रहा। मंच पर केंद्रीय और राज्य स्तर के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जिनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार , भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा,सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी,भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिप अध्यक्ष यशवंत बबलू मीणा, नपाध्यक्ष सविता जमना सेन जनपद अध्यक्ष अर्चना सुनील पोर्ते सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

नितिन गडकरी ने की शिवराज चौहान की तारीफ

नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में आगे है, शिवराज चौहान का किया काम देश ने रिकनाइज किया है, यूपीए सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया है। उन्होंने किसानों को उन्नत करने के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन किया है, ये ऐसे भविष्य की प्रेरणा देगा जो आपके जीवन से गरीबी और भूखमरी को दूर करेगा। देश के किसान खुशहाल और संपन होगें और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है और ये सपना किसानों के बगैर पूरा नहीं होगा और उस सपने को पूरा करने में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की भूमिका अहम होगी।

कृषि मंत्री शिवराज चौहान का कार्य और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी-शिवराज

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो सपना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाकर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, वह किसानों के बिना संभव नहीं हो सकता। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्य और उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मैं 'उन्नत कृषि मेले के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ।

कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से किसानों को सीधे जोड़कर पारदर्शिता और लाभ सुनिश्चित किया गया है। साथ ही उन्होंने सूखे की स्थिति में धान की वैकल्पिक रोपाई तकनीकों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की बात भी उन्होंने कही, जिससे किसानों की लागत कम और आय में वृद्धि संभव है।

महोत्सव में केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए गए। 'धरती बचाओ, जीवन बचाओ' विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति ने पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और जंगलों की कटाई रोकने जैसे मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने रखा। इसने किसानों और आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया।

नाके पर पुलिस ने रुकवाई बाइक....तलाशी के दौरान मिला कुछ ऐसा कि जेल पहुंच गए 2 युवक

बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर थाना की पुलिस ने 14.44 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जयनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बाताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि कुछ युवक ब्राउन शुगर लेकर कमला बांध ईसलामपुर के रास्ते जाने वाले है। इस सूचना के आधार पर ईसलामपुर मुहल्ला के कमला पश्चिमी तटबंध पर वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान देखा गया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आ रहे हैं। बाइक सवार लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि तलाशी के दौरान उक्त युवकों के पास से 14.44 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद किया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवकों की पहचान मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव निवासी श्याम पांडेय एवं नेपाल के धनुषा जिले के नगराई थाना क्षेत्र के गंगोली गांव निवासी संतोष कुमार ठाकुर के रूप में की गई है। गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ईंधन की कीमतों पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा- भारत में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन भारत इस संकट से सुरक्षित है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय विदेश नीति और भारत के अन्य देशों के साथ मजबूत संबंधों को दिया। 'दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा है और कई देशों में ईंधन की भारी किल्लत है, लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत यह है कि हमारे जहाज आज भी होर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित गुजर रहे हैं।

भ्रामक खबरों पर किया कटाक्ष

रक्षा मंत्री ने उन तत्वों पर भी निशाना साधा जो तेल की कीमतों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने होर्डिंग और विज्ञापनों के जरिए दुष्प्रचार करने की कोशिश की, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और घरेलू अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

वृंदावन नाव हादसा: मौत का आंकड़ा 14 पहुंचा... लुधियाना के 2 सगे भाई-बहन के शव बरामद, अब भी 2 की तलाश जारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धर्मनगरी वृंदावन में बीते शुक्रवार को यमुना नदी में हुए भीषण नाव हादसे के तीसरे दिन भी मातम छाया हुआ है। रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 और शव बरामद होने के साथ ही इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 14 हो गई है। नदी में अब भी 2 अन्य श्रद्धालुओं की तलाश के लिए महा-अभियान जारी है।

नदी की सतह पर मिले भाई-बहन के शव

रविवार की सुबह रेस्क्यू टीम को पंजाब के लुधियाना निवासी 2 और शव नदी की सतह पर तैरते मिले। मृतकों की पहचान डिंकी और ऋषभ शर्मा के रूप में हुई है। डिंकी बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी और ऋषभ ने अभी 12वीं की परीक्षा पास की थी। दोनों भाई-बहन परिवार के साथ दर्शन करने आए थे, लेकिन काल के गाल में समा गए। शव फूलने के कारण पानी के ऊपर आ गए थे, जिन्हें गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।

20 किलोमीटर के दायरे में महा-रेस्क्यू

हादसे के तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सेना, एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF) और पीएसी के करीब 250 जवान इस अभियान में जुटे हैं। इस नाव हादसे में अब तक 22 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए गोताखोर गहरे पानी और झाड़ियों में सर्च कर रहे हैं।

शोक में डूबा परिवार

परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अपने प्रियजनों के शवों की पहचान की, जिसके बाद घाट पर चीख-पुकार मच गई। इससे पहले शनिवार को भी मानिक टंडन नाम के युवक का शव देवरहा बाबा घाट के पास मिला था। प्रशासन का कहना है कि जब तक आखिरी व्यक्ति की तलाश पूरी नहीं हो जाती, ऑपरेशन खत्म नहीं होगा।

संक्षिप्त ख़बरें

गोंडा में न्यायिक फेरबदलः अलका यादव अपर प्रधान न्यायाधीश, शबीना खान बनीं सिविल जज

गोंडा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिले में अपर जिला जज के पद पर कार्यरत अलका यादव को अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शबीना खान को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक फर्रुखाबाद से गोंडा स्थानांतरित एडीजे संदीप तिवारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, सहारनपुर से स्थानांतरित आलोक शर्मा को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट व महाराजगंज से स्थानांतरित अपर जिला जज फूलचंद्र कुशवाहा को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट बनाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गोंडा विकास को 14वें वित्त आयोग के तहत सृजित न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सूर्य प्रकाश सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट दानिश हसनैन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार बिजनौर से स्थानांतरित अंशुमन धुन्ना को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज से आए अनुराग को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिरोजाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहीं श्वेता सोनी को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, बिजनौर से स्थानांतरित सिविल जज जूनियर डिवीजन साधना कुमारी को कर्नलगंज, सहसवान बदायूं के अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक कुमार तृतीय को तरबगंज और फिरोजाबाद से स्थानांतरित प्रभात कुमार सिंह को ग्राम न्यायालय मनकापुर में न्यायाधिकारी बनाया है।

वहीं, गोंडा जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबुज मिश्रा को सिविल जज जूनियर डिवीजन, आकांक्षा सिंह को अंबुज मिश्रा के स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अनूप कुमार को आकांक्षा सिंह के स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नियुक्त किया गया है।

नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को योगी ने बताया साजिश, अखिलेश बोले- मजदूरों के जख्मों पर नमक न छिड़कें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब प्रदेश विकास और शांति की ओर बढ़ रहा है तो कुछ लोग षड्यंत्र फैलाने का काम कर रहे हैं. हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है. उद्यमियों को सुरक्षा और हर श्रमिक को संरक्षण भी देंगे. योगी के इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं. आप मजदूरों के जख्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो न लगाएं लेकिन उन जख्मों पर नमक तो न छिड़कें. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुजफ्फरनगर में 951 करोड़ रुपये की 423 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और सेवा का एक मजबूत मॉडल प्रस्तुत कर रही है. मगर कुछ लोग साजिश के तहत अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं।

हमारी सरकार श्रमिकों के साथ- CM योगी

सीएम योगी ने प्रदेश के श्रमिकों से अपील की कि वे औद्योगिक अशांति फैलाने वालों से सावधान रहें और उनके प्रयासों को किसी भी कीमत पर सफल न होने दें. डबल इंजन सरकार विकास और विरासत की यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ा रही है, जिसमें श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है. सरकार उद्यमियों को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी प्रदान करेगी, साथ ही उनका उचित मानदेय सुनिश्चित करेगी. हमने पिछले साल ही एक कॉरपोरेशन का गठन कर दिया है और इसी महीने उसकी सिफारिशें लागू होने वाली हैं।

अखिलेश ने किया पलटवार

सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी नोएडा के मज़दूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं तो एक सवाल जनता आपसे पूछ रही है कि अगर ये सच है तो आपकी खुफिया पुलिस क्या आपके साथ बंगाल प्रचार करने गई थी या वनस्पति की खोजबीन में लीन थी या उसके प्रभाव में. मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद के आरोप से बदनाम करने से पहले आप ये बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि 10 सालों में ऐसे हालात बन गए. अखिलेश ने कहा कि आप मजदूरों के जख्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो न उस पर नमक तो न छिड़कें. भाजपाई कमीशनखोरी से जन्मी महंगाई के कारण परिवारवाले वैसे ही दुखी है उसके ऊपर अवांछित दोषारोपण करने का जो पाप आप कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है. इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं. अखिलेश ने आगे कहा कि अगर आप से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो ससम्मान इस गद्दी से उतरकर जाइए।

सरकार ने गठित की हाई लेवल कमेटी

बता दें कि नोएडा में बढ़ते श्रमिक आंदोलन और औद्योगिक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है. यह समिति श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच संवाद स्थापित कर हालात सामान्य करने की कोशिश करेगी. नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों स्तर पर तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं. नोएडा के कई इलाकों में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था. कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिली।

गाजियाबाद रेप केसः FIR में देरी और धाराओं पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गाजियाबाद में बच्चे के रेप केस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 3 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी. एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है. एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने इससे पहले मामले का उल्लेख करते हुए पुलिस कमिश्नर को जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई थी. बेंच ने अनुमति दे दी. एसीपी और संबंधित एसएचओ को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह चिंताजनक है कि जब कोई अदालत में आता है, तो आप कहते हैं कि आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है. एएसजी भाटी ने कहा कि यहां याचिका दायर होने से पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन, जो याचिकाकर्ता के लिए- निर्देशों के बावजूद उन्होंने अस्पतालों को नोटिस नहीं दिया है. पुलिसकर्मियों ने बयान दर्ज किए हैं कि बच्चा सांस नहीं ले रहा था. वीडियो कुछ और ही दिखाता है. विशेष जांच समिति की आवश्यकता है. यह एक दिखावटी प्रयास है।

कोर्ट में एएसजी भाटी ने कही ये बात

एएसजी भाटी ने कहा कि अस्पतालों को भी नोटिस दिया है. न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि क्या रक्त और अन्य तरल पदार्थ डीएनए जांच के लिए भेजे गए थे? एएसजी ने कहा कि जी हां, भेजे गए थे. हरिहरन ने कहा कि घटना 16 मार्च को हुई थी और 18 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. सुबह 3:30 बजे एफआईआर क्यों दर्ज की गई? एफआईआर में केवल धारा 302 का उल्लेख है. गंभीर यौन उत्पीड़न आदि का कोई जिक्र नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृपया स्थिति रिपोर्ट की जांच करें. एसआईटी के गठन की अत्यधिक जल्दबाजी में हमें प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए. हरिहरन ने कहा कि जब मजदूर ने मामला दर्ज कराने की कोशिश की, तो उसे पुलिस स्टेशन में पीटा गया. उसे अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है. उन्होंने उस वीडियो को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया है जिसमें बच्चा जीवित दिख रहा है. वे इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चा मर चुका है।

कोर्ट ने आरोपपत्र की जांच का दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र की जांच करें और देखें कि उन्होंने किस वीडियो पर भरोसा किया है. इसकी जांच करें और हमें बताएं कि क्या इसमें कोई खामी रह गई है. यदि खामियों के कारण एसआईटी की आवश्यकता है, तो हम एसआईटी का आदेश देंगे. सीजेआई ने आदेश में दर्ज किया कि मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है. हम मामले को अभी बंद नहीं कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि बहुत आशंकाएं प्रतीत होती हैं लेकिन हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है. 10 अप्रैल के हमारे आदेश में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करने से पहले, याचिकाकर्ता को स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए. याचिकाकर्ता को वीडियो आदि भी उपलब्ध कराए जाएं. इस बीच प्रतिवादी अस्पतालों को भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. आगे कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा।

अमित शाह ने दुर्गापुर में किया रोड शो, कहा- भाजपा सरकार बनने पर बंगाल में खत्म होगा 'गुंडाराज'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शाह ने बीरभूम के बोलपुर में एक रैली को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर जन समर्थन मांगा। शो के दौरान उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पर के जाने के बाद पश्चिम बंगाल से 'गुंडाराज' और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि चार मई के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शाह ने बीरभूम के बोलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 2021 के चुनावों के बाद इस क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारी अत्याचार किए गए। उन्होंने मतदाताओं से ममता बनर्जी सरकार को विदा करने का आह्वान करते हुए वादा किया कि गिरोह और 'कमीशन' प्रथाओं में शामिल लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे।' उन्होंने दावा किया कि 'डबल इंजन सरकार' राज्य में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी।

शाह ने कथित उपद्रवियों को चेतावनी दी कि वे 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन घरों के अंदर रहें, अन्यथा पांच मई के बाद उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल की जनता बमों का जवाब मतपत्रों से देगी और डर का जवाब भरोसे से देगी।' शाह ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर दावा किया कि जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं का पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने तृणमूल नेताओं पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया और मयूरेश्वर जैसे क्षेत्रों में खराब बुनियादी ढांचे की ओर इशारा किया। उन्होंने भर्ती, राशन वितरण, मनरेगा और आवास योजनाओं में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया।

केंद्रीय मंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की और वादा किया कि बंगाल को महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित बनाया जाएगा कि वे रात में भी बेखौफ बाहर निकल सकें। उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया और घुसपैठ रोकने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि चार मई के बाद घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा। इससे पहले, बोलपुर के पल्लीमंगल क्लब मैदान में अपनी पहली रैली के दौरान शाह ने सुरक्षाकर्मियों से लोगों को बिना जांच के प्रवेश करने देने के लिए कहकर एक विशेष संदेश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद केडीए हुआ सतर्क, अब फाइलों का होगा सत्यापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद केडीए अफसर सतर्क हुए हैं। फाइलों का सत्यापन कराया जा रहा है। खास तौर पर कोर्ट से जुड़े मामलों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। पनकी, इंदिरा नगर, कल्याणपुर व साकेत नगर योजनाओं से जुड़े दस्तावेज प्राधिकरण से गायब हैं। मूल आवंटी समस्याओं के निस्तारण के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन फाइल न होने के कारण मामले लटके हैं। जूही योजना में हाई कोर्ट ने आवंटी की शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए थे लेकिन कर्मचारी राजेश कुमार और रजनीश दस्तावेज व कागज दबाए रहे।

इसके चलते उपाध्यक्ष व सचिव के नाम जमानती वारंट जारी हो गया। 11 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद मामला सामने आया। दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। अब कर्मचारियों की जांच कराई जा रही है।

पनकी व इंदिरा नगर योजना में केडीए के भूखंडों को फर्जी दस्तावेज लगाकर दूसरों के नाम सक्रिय रैकेट ने आवंटन कर दिया है। कई मामले पकड़े भी गए। अब भी तमाम मामले लटके हुए है। पनकी योजना व इंदिरा नगर योजना में केडीए के भूखंड पर लोगों ने कब्जा करके गेस्ट हाउस, होटल, अपार्टमेंट व शापिंग कांप्लेक्स बना लिए हैं। इस खेल में केडीए के ही कर्मचारी शामिल हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अब भी चोरी-छिपे कार्य देख रहे हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि जांच की जा रही है। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

नया भारत, नई संसद: जहां निर्णयों में नारी दृष्टि होगी केंद्र में

[2029 की लोकसभा — जब आधी आबादी बनेगी असली शक्ति]
[संसदीय सिस्टम रीसेट: प्रतिनिधित्व नहीं, अब वास्तविक शक्ति का इंस्टॉलेशन]

इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने को तैयार एक नया अध्याय अब आकार ले रहा है, जहां भारतीय लोकतंत्र अपनी सबसे बड़ी कमी को सुधारने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। 8 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में संशोधन को हरी झंडी मिलना महज़ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के पुनर्जागरण का संकेत है। 2029 के आम चुनाव के साथ ही जब यह व्यवस्था लागू होगी, तो लोकसभा का चेहरा पूरी तरह रूपांतरित नजर आएगा। यह बदलाव केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस असंतुलन को खत्म करने का सशक्त प्रयास है, जिसने लंबे समय तक देश की आधी आबादी को सत्ता और निर्णय की मुख्य धारा से अलग-थलग रखा।

नवाचार और संतुलन के मेल से तैयार यह खाका बदलाव की सशक्त तस्वीर पेश करता है, जिसमें साहस के साथ संवेदनशीलता भी झलकती है। सबसे अहम बात यह है कि किसी मौजूदा सांसद की सीट छीने बिना महिलाओं के लिए व्यापक स्थान सुनिश्चित किया गया है। 543 से बढ़कर 816 सीटों तक का विस्तार केवल संख्या वृद्धि नहीं, बल्कि लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने की पहल है, जहां '50+33' का फार्मूला दूरदर्शी समाधान बनकर उभरता है। एक-तिहाई यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, और यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से लागू होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी उनके हिस्से में भागीदारी देकर इस बदलाव को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है, जिससे यह पहल राजनीतिक बदलाव के साथ व्यापक सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है।

जब आंकड़े ही बदलाव की आवाज बन जाएं, तो सियासत की दिशा बदलना तय हो जाता है—और यही तस्वीर 2029 में उभरने वाली है, जब संसद में हर तीसरी आवाज महिला की होगी। आज जहां महिलाओं की मौजूदगी सीमित है, वहीं यह उछाल केवल संख्या का विस्तार नहीं, बल्कि सोच, सरोकार और फैसलों के तरीके में गहरा बदलाव लाएगा। बहसों की दिशा बदलेगी, प्राथमिकताएं नए सिरे से तय होंगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी। अब तक किनारे पर पड़े मुद्दे—जैसे महिला सुरक्षा, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य—नीति के केंद्र में आ जाएंगे। संसद का स्वर अधिक संतुलित, संवेदनशील और विविधतापूर्ण होगा, जहां नीतियां आंकड़ों से आगे बढ़कर जीवन के वास्तविक अनुभवों की जमीन पर आकार लेंगी।

नीति निर्माण की धुरी अब केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज की वास्तविक पीड़ा और जरूरतों को केंद्र में रखकर घूमेगी। यह परिवर्तन एक ऐसी संवेदनशीलता को जन्म देगा, जहां कानून सीधे लोगों के जीवन से संवाद करते नजर आएंगे। मातृ स्वास्थ्य से लेकर बालिका शिक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा तक, हर क्षेत्र में ठोस और प्रभावी पहल का विस्तार होगा। जो समस्याएं अब तक ग्रामीण महिलाओं के हिस्से में चुपचाप सिमटी रहती थीं, वे अब नीतियों की आधारशिला बनेंगी। इसके परिणामस्वरूप योजनाओं का स्वरूप ही नहीं बदलेगा, बल्कि उनके क्रियान्वयन में भी गति, जवाबदेही और पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

सियासी गलियारों में अब जीत की गणित से आगे बढ़कर नेतृत्व की गुणवत्ता की कसौटी तय होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक दलों के सामने केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सक्षम महिला नेतृत्व गढ़ना भी अनिवार्य बन जाएगा। उम्मीदवारों के चयन से लेकर उनके प्रशिक्षण और संसदीय कौशल को निखारने तक, हर स्तर पर गंभीरता बढ़ेगी। बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच महिला उम्मीदवारों को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज होगी, जिससे राजनीति में गुणवत्ता और जवाबदेही का स्तर स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठेगा। यह परिवर्तन नई पीढ़ी की महिलाओं के लिए राजनीति के द्वार खोलेगा, जो अपने साथ नई दृष्टि, आत्मविश्वास और ऊर्जा लेकर सार्वजनिक जीवन में कदम रखेंगी।

जब निर्णय की मेज पर तस्वीर बदलती है, तो समाज का चेहरा भी बदलना तय हो जाता है—और यही असर इस परिवर्तन का होगा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परिवार, शिक्षा और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में नई दिशा तय करेगी। गांवों और शहरों में बेटियों के सपनों को नई ऊंचाई मिलेगी और उनके भीतर यह विश्वास मजबूत होगा कि वे भी देश के सर्वोच्च मंच तक अपनी पहचान बना सकती हैं। लंबे समय से जकड़ी पितृसत्तात्मक सोच धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगी और उसकी जगह समानता, सम्मान और संतुलन पर आधारित नया सामाजिक ढांचा मजबूती से उभरकर सामने आएगा।

परिवर्तन जितना विराट होता है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती है—और यही चुनौती इस ऐतिहासिक कदम के साथ सामने आएगी। इतनी बड़ी संख्या में नई महिला सांसदों को प्रभावशाली और सक्षम नेतृत्व में ढालना आसान नहीं होगा। इसके लिए संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ, सटीक संवाद कौशल और मजबूत राजनीतिक रणनीति का विकास अनिवार्य होगा। साथ ही सुरक्षा, पर्याप्त संसाधन और सशक्त सहयोगी तंत्र सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि ये प्रतिनिधि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकें। यदि इन पहलुओं पर गंभीरता और दूरदर्शिता के साथ काम किया गया, तो यह बदलाव केवल प्रतीक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में स्थायी और प्रभावशाली परिवर्तन की नींव रखेगा। लोकतांत्रिक परिवर्तन की यह यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां 2029 की लोकसभा भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम और निर्णायक अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही है। यहां प्रतिनिधित्व केवल आंकड़ों का संतुलन नहीं रहेगा, बल्कि न्याय, समानता और वास्तविक भागीदारी की सशक्त चेतना बनकर उभरेगा। यह वह ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश अपनी आधी आबादी को निर्णय निर्माण की पूर्ण शक्ति और अवसर प्रदान करेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी, संवेदनशील और सशक्त स्वरूप ग्रहण करेगा। महिला आरक्षण कानून अब केवल एक विधायी व्यवस्था नहीं, बल्कि उस नए भारत का स्पष्ट और अटल संदेश बन चुका है, जो समानता, सहभागिता और प्रगति के पथ पर दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

अप्रैल की भीषण गर्मी और अनियमित वर्षा से बदलता जीवन का संतुलन

देशभर में मौसम का असामान्य रूप और जनजीवन पर प्रभाव

अप्रैल का महीना इस बार अपने साथ ऐसा मौसम लेकर आया है, जिसने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। एक ओर उत्तर भारत में गर्मी का पारा तेजी से चढ़ रहा है और दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में वर्षा और तूफान का दौर जारी है। इस कारण जनजीवन पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तेज धूप का सामना करना पड़ता है और दोपहर तक गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ।शाम के समय भी राहत नहीं मिलती और रात में भी गर्मी बनी रहती है। इससे लोगों की नींद और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर कई राज्यों में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हो जाती है। जिससे कामकाज रुक जाता है और लोगों को असुविधा होती है।

उत्तर भारत में इस समय गर्मी लगातार बढ़ रही है। राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिल्ली हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है ।कई शहरों में तापमान चालीस डिग्री के आसपास पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसके बयालीस डिग्री तक जाने की संभावना है। इस कारण दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा है। लोग केवल जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलते हैं और अधिकतर समय घरों में ही रहते हैं। गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है और थकान चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

राजस्थान में गर्मी का असर और अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जयपुर कोटा उदयपुर बाड़मेर और जोधपुर जैसे शहरों में तापमान तेजी से बढ़ा है ।बाड़मेर और कोटा में पारा उनतालीस डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दिन के साथ अब रात में भी गर्मी का असर बना रहता है। जिससे लोगों को राहत नहीं मिलती। जल स्रोतों पर दबाव बढ़ गया है और कई क्षेत्रों में पानी की कमी महसूस की जा रही है। बाजारों में दिन के समय भीड़ कम हो गई है और लोग सुबह और शाम के समय ही अपने कार्य पूरे करने का प्रयास करते हैं।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना जताई है ।तापमान में वृद्धि के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। खुले में काम करने वाले मजदूर और किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। विद्यालयों में भी बच्चों के समय में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि उन्हें इस तेज गर्मी से बचाया जा सके।

जहां एक ओर उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में वर्षा और तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश मेघालय मणिपुर नगालैंड और त्रिपुरा में आंधी और वर्षा की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक और केरल में भी कई स्थानों पर तेज वर्षा हुई है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात प्रभावित हुआ है। अचानक मौसम बदलने से लोगों को अपने कार्यों में बार बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा है।

देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है और तापमान शून्य से नीचे चला गया है। यह स्थिति मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से बिल्कुल अलग है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति कितनी भिन्न है।

जम्मू के अखनूर क्षेत्र में बवंडर जैसी दुर्लभ घटना भी देखी गई जो कुछ समय तक चली हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन इसने लोगों को चौंका दिया। इस प्रकार की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि मौसम में अस्थिरता बढ़ रही है और प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है।

मौसम के इस बदलते स्वरूप का सबसे अधिक असर कृषि पर पड़ रहा है तेज गर्मी के कारण फसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और उत्पादन में कमी आने की आशंका है ।वहीं अचानक वर्षा से कटाई के समय फसल खराब हो सकती है किसानों के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन हो गई है उनकी मेहनत पर मौसम का सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय चुनौतीपूर्ण है गर्मी और उमस के कारण शरीर में पानी की कमी हो रही है और कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह समय विशेष रूप से कठिन है। चिकित्सकों के अनुसार इस मौसम में अधिक पानी पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए।

आने वाले दिनों में मौसम के और अधिक कठोर होने की संभावना है। उत्तर और मध्य भारत में तापमान बयालीस डिग्री तक पहुंच सकता है, वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में वर्षा और तूफान का दौर जारी रह सकता है। इस कारण लोगों को सावधानी बरतनी होगी और अपने कार्यों को मौसम के अनुसार ढालना होगा।

अप्रैल का यह महीना इस बार मौसम के दोहरे प्रभाव के कारण कठिन बन गया है एक ओर भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और दूसरी ओर वर्षा और तूफान नई समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। यह स्थिति केवल एक मौसमी बदलाव नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास करने होंगे तभी हम इस प्रकार की परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

कांतिलाल मांडोत

बंगाल चुनाव में भरोसे का दांव और लोकतंत्र में संवाद की सशक्त झलक

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह विश्वास और पहचान की व्यापक परीक्षा बन गया है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति को भरोसे की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने पूर्व बर्द्धमान के कटवा मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी में आयोजित जनसभाओं में जनता से संवाद करते हुए ममता बनर्जी सरकार के पंद्रह वर्षों के कार्यकाल को अन्याय का काल बताया और केवल पांच वर्षों का अवसर मांगा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठ को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब गंभीर रूप ले चुकी है और राज्य की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और राज्य की पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने चुनाव को बंगाल की पहचान को बचाने की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में तेजी से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने मूल नारे से हटकर अब केवल सत्ता बनाए रखने के लिए नए समीकरणों पर निर्भर हो गई है। यह बयान मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास भी माना जा रहा है।

कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता का हक खाएंगे उनके लिए अब सम्मान नहीं होगा बल्कि जेल के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और जनता के सामने पूरा विवरण रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भय का वातावरण समाप्त कर अवसर और विकास का नया युग शुरू किया जाएगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने बर्द्धमान की कृषि परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कभी समृद्धि का प्रतीक था लेकिन अब अपनी पहचान खो चुका है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जहां महिलाएं बिना भय के जीवन जी सकें। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही उन्होंने शरणार्थी समुदायों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सके।

प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान तकनीकी माध्यमों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल कृत्रिम साधनों के माध्यम से भ्रामक संदेश फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। यह बयान आधुनिक चुनावी प्रक्रिया में तकनीक की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है।

जहां एक ओर बंगाल में राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक संवाद की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। संसद भवन परिसर में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि सामान्यतः दोनों नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर केवल औपचारिक अभिवादन करते ही देखा जाता है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ क्षणों के लिए बातचीत भी की। हालांकि बातचीत का विषय स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन यह दृश्य अपने आप में लोकतांत्रिक परंपरा का एक सकारात्मक संकेत था।

यह घटना यह दर्शाती है कि भारतीय लोकतंत्र में मतभेदों के बावजूद संवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भी आपसी सम्मान और संवाद की संस्कृति लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। यह केवल एक औपचारिक क्षण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रतीक भी है।

समग्र रूप से देखा जाए तो बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं है बल्कि यह विश्वास पहचान और विकास के मुद्दों के बीच एक व्यापक संघर्ष है। प्रधानमंत्री का भरोसे की राजनीति का आह्वान और विपक्ष के साथ संवाद की झलक दोनों यह संकेत देते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संवाद दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता इन संदेशों को किस प्रकार ग्रहण करती है और किस दिशा में अपना निर्णय देती है।

कांतिलाल मांडोत

असंयम कुप्रबंधन लापरवाही के चलते जान गंवाते श्रद्धालु!

अभी बिहार के नालंदा के देवी मंदिर धर्मस्थल पर भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत का मामला ठंडा भी नही हुआ कि उत्तर प्रदेश के बड़े तीर्थ स्थल मथुरा के निकट वृंदावन में नाव हादसे का बेहद दुखदायी हादसा सामने आया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और अभी कुछ लापता भी हैं। आए दिन कभी पवित्र नदियों के स्नान पर्व पर कभी मंदिरों में दर्शन अवसर पर तो कभी तीर्थ यात्रा और तीर्थ स्थलों कभी शोभा यात्रा पुरी रथयात्रा रामलीला मेलों या गणेश मूर्ति विसर्जन के मौके पर हो रहे हादसों में सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान जा रही है हर हादसे के बाद जांच की खाना पूर्ति की जाती है हर बार प्रबंधन की खामियां प्रशासन की लापरवाही सामने आती है लेकिन कोई बदलाव नहीं आता इससे पहले अगला हादसा हो जाता है।

आपको बता दें वृंदावन एक ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां लाखों ही लोग जाते हैं। यहां भगवान कृष्ण जी ने अपना बचपन गुज़ारा। उनका जन्म मथुरा में हुआ। वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं। यमुना के किनारे बसा होने के कारण यहां अनेक ही घाट हैं। यहां भगवान कृष्ण की याद में बना बांके बिहारी मंदिर लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र बना रहता है। पंजाब से भी कुछ दर्जन श्रद्धालु यहां गए थे और लुधियाना, मुक्तसर एवं जगराओं के लगभग 37 श्रद्धालु यमुना में एक मोटर बोट पर सवारी कर रहे थे।

गहरे पानी में बने पाटून पुल जिसे अब हटाया जा रहा था, से श्रद्धालुओं की नाव टकरा गई, जिस कारण यह हादसा हो गया, परन्तु नज़दीक के नाव वालों और गोताखोरों ने इनमें से कई व्यक्तियों को बचा लिया। इससे पहले भी देश भर में ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए पूरे प्रबन्ध न किये जाने के कारण अक्सर हादसे हो जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग शिकार हो जाते हैं। इस तरह के प्रत्येक बड़े हादसे के बाद विशेष रूप से मेलों और धार्मिक स्थलों पर एकत्रित हुए श्रद्धालओं संबंधी पुख्ता प्रबन्ध करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। इन प्रबन्धों का कुछ प्रभाव भी पड़ता है। फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इन प्रबन्धों में त्रुटियां रह जाने के कारण या प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण ऐसे दुखद हादसे घटित हो जाते हैं। ऐसा कुछ न घटित हो, इसकी ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों पर भी आती है। उनकी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे प्रत्येक पक्ष से सचेत होकर प्रबन्ध करें, जिनसे श्रद्धालुओं की बड़ी से बड़ी संख्या को भी नियंत्रित किया जा सके, ताकि ऐसे हादसे न घटित हों। यमुना नदी की सैर करते हुए अथवा यहां एक से दूसरे स्थान पर नावों द्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को सचेत होने की ज़रूरत है। जिस समय यह हादसा घटित हुआ, उस समय मोटर बोट में 31 श्रद्धालु थे, जिनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। यह बात सुनिश्चित है कि यदि मोटर बोट के प्रबन्धकों या प्रशासन की ओर से नाव में बैठने वालों के लिए लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी किया जाता तो मरने वालों में ज्यादातर का बचाव होने की बड़ी सम्भावना थी।

इस संबंध में सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी धार्मिक या अन्य त्यौहार पर अथवा यदि किसी स्थान पर भारी जनसमूह जमा होने की सम्भावना हो, तो वह विशेष प्रबंध किए जाने के निर्देश दे और स्थानीय सरकारें द्वारा किए गए प्रबन्धों संबंधी भी केन्द्र सरकार से संबंधित अधिकारियों द्वारा सम्पर्क बनाए रखना ज़रूरी होना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री द्वारा और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रभावित परिवारों के लिए राहत की घोषणा की गई है परन्तु ऐसे हादसों के कारण लम्बी अवधि तक संबंधित परिवारों को बड़ी त्रासदी भोगनी पड़ती है। समाज के सभी वर्गों और प्रशासनों को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ घटित न हो वहीं श्रद्धालुओं को भी पर्याप्त सावधानी और उत्साह के अतिरेक से बचना चाहिए एक ही दिन एक ही अवसर पर क्षमता से अधिक लोगों का एक स्थान पर स्नान पूजा मेला कथा शोभायात्रा में जमावड़ा करना और संयम खो कर धक्का मुक्की कर व्यवस्था बिगाड़ना कौन सी धार्मिकता का परिचय देता है? हर आयोजन में दो चार फीसदी ऐसे उश्रृंख लोगों की मौजूदगी रहती है जो अनावश्यक टकराव और अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग न भक्त हो सकते हैं न श्रद्धालु ये सिर्फ धार्मिक चोला पहन कर उन्माद मचाने का काम करते हैं और सच्चे श्रद्धालुओं के जीवन के लिए खतरा पैदा करने का काम करते हैं ऐसे ही लोग कांवड़ियों के वेश में शामिल होकर की बार उपद्रव करने का प्रयास करते हैं।सभी श्रद्धालुओं का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था बना रही पुलिस मंदिर कमेटी के स्वयं सेवकों के निर्देशानुसार संयमित व्यवहार करें आपाधापी लाइन तोड़ कर आगे बढने की स्वार्थी प्रवृति से बचना चाहिए वही धार्मिक उपदेशक कथा वाचक भी अपने अनुयायियों को इन अवसरों पर नैतिकता संयम बनाने के लिए आगाह कर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।कोई भी हादसा अनेक जीवन खासकर महिलाओं बच्चो के जीवन को खत्म कर परिवार को न भूलने वाला दुख देता है इस को टाला जा सकता है।

मनोज कुमार अग्रवाल

लोकतंत्र की पुनर्रचना: आरक्षण, परिसीमन और भारत का भविष्य

भारत का लोकतंत्र सदैव एक जीवंत और गतिशील प्रयोग रहा है ऐसा प्रयोग जो अपनी विविधता, अपनी जटिलता और अपनी अंतर्विरोधों के साथ भी निरंतर आगे बढ़ता रहा है। स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षों से अधिक की यात्रा में यह लोकतंत्र अनेक परीक्षाओं से गुजरा है, अनेक संकटों को पार किया है और अनेक ऐतिहासिक मोड़ों पर खड़ा रहा है। किंतु वर्तमान समय जो प्रश्न उठा रहा है, वह केवल नीति या विधान का प्रश्न नहीं है यह उस मूलभूत प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है कि क्या भारत अपनी आधी जनसंख्या को वास्तविक शासन-सत्ता में भागीदार बनाने के लिए सचमुच तत्पर है। यह प्रश्न महिला आरक्षण और परिसीमन के उस संयुक्त विमर्श से उभरा है, जो आज भारतीय राजनीति के केंद्र में है। इसे समझने के लिए पहले उस स्थिति को देखना आवश्यक है जो दशकों से बनी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात जब प्रथम लोकसभा गठित हुई, तब उसमें केवल बाईस महिला सदस्य थीं। यह संख्या तब से अत्यंत धीमी गति से बढ़ी है। 17वीं लोकसभा में यह लगभग 15% के आसपास ही पहुँची। राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ अनेक राज्यों में महिला विधायकों का औसत दस प्रतिशत से भी कम है। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया बुलाया है। इस दौरान संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव ला सकती है। इसके तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 हो जाएगी।

इसी असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से संसद ने वह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पारित किया जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत लोकसभा और समस्त राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई अर्थात तैंतीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा, जिसका अर्थ यह है कि सामाजिक न्याय की दोहरी परत इस व्यवस्था में समाहित है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि जब किसी विधायिका में महिलाओं की भागीदारी तीस प्रतिशत के आसपास पहुँचती है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर नीति-निर्माण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जाता है। रवांडा जैसे देश, जहाँ संसद में महिलाओं की भागीदारी साठ प्रतिशत से अधिक है, इसके जीवंत उदाहरण हैं।

किंतु इस अधिनियम का सबसे विवादास्पद पक्ष इसका कार्यान्वयन है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा, बल्कि इसे आगामी जनगणना और उसके पश्चात होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। वर्तमान संकेतों के अनुसार इसे वर्ष दो हजार उनतीस के आम चुनाव तक लागू करने की योजना है। इस विलंब ने अनेक राजनीतिक दलों और महिला संगठनों में असंतोष उत्पन्न किया है। उनका तर्क है कि जो अधिकार न्यायसंगत है और जिसकी आवश्यकता स्वीकार की जा चुकी है, उसे किसी तकनीकी प्रक्रिया के अधीन क्यों बनाया जाए।

परिसीमन की प्रक्रिया स्वयं में एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील विषय है। इसका सरल अर्थ है जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ताकि प्रत्येक प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे और लोकतंत्र की मूल भावना एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य सुनिश्चित हो सके। भारत में अंतिम व्यापक परिसीमन उन्नीस सौ इकहत्तर की जनगणना के आधार पर किया गया था। उसके बाद यह प्रक्रिया इस उद्देश्य से स्थगित कर दी गई कि यदि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में सीटें बढ़ाई गईं, तो परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को राजनीतिक हानि उठानी पड़ेगी। यह स्थगन एक नैतिक निर्णय था, किंतु अब जब पाँच दशक से अधिक समय बीत चुका है और जनसंख्या का वितरण नाटकीय रूप से बदल चुका है, तो परिसीमन की अनिवार्यता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता।

वर्तमान जनसंख्या आँकड़ों पर दृष्टि डालें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग पच्चीस करोड़ से अधिक है, बिहार की लगभग तेरह करोड़, जबकि केरल की जनसंख्या लगभग साढ़े तीन करोड़ और तमिलनाडु की लगभग साढ़े सात करोड़ है। यदि परिसीमन पूर्णतः जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उत्तर भारत के राज्यों को संसद में अनेक अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत घट सकती है। दक्षिण के राज्यों का तर्क यह है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट

प्रदर्शन किया, राज्य की नीतियों का अनुपालन किया और अब उन्हें इसी अनुपालन के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह केवल संख्याओं का विवाद नहीं है यह उस संघीय भावना का प्रश्न है जिसके आधार पर भारत का ताना-बाना बुना गया है।

इस संकट से निपटने के लिए एक प्रस्ताव यह आया है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। वर्तमान में लोकसभा में पाँच सौ तैंतालीस निर्वाचित सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह संख्या आठ सौ या इससे भी अधिक तक जा सकती है। इस वृद्धि का तर्क यह है कि यदि सीटों की कुल संख्या बढ़ाई जाए, तो किसी भी राज्य की वर्तमान सीटें घटाए बिना नई जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इससे दक्षिण भारत के राज्यों की आशंका कुछ हद तक कम हो सकती है। किंतु इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या आठ सौ या उससे अधिक सदस्यों वाली संसद प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है, क्या विधायी विमर्श की गुणवत्ता बनी रह सकती है और क्या नई संसद भवन इतनी बड़ी संख्या को समायोजित करने में सक्षम होगा। नए संसद भवन में एक हजार से अधिक सदस्यों की बैठने की व्यवस्था इस दिशा में एक दूरदर्शी तैयारी के रूप में देखी जा सकती है।

महिला आरक्षण और सीट-वृद्धि का यह संयोजन भारतीय दलीय राजनीति के भीतर भी गहरे परिवर्तन उत्पन्न करेगा। प्रत्येक दल को अपनी एक-तिहाई सीटें महिला प्रत्याशियों के लिए सुनिश्चित करनी होंगी। यह व्यवस्था उन महिलाओं के लिए अवसर का द्वार खोलेगी जो प्रतिभावान हैं, सक्रिय हैं, किंतु दलीय संरचना के भीतर टिकट पाने में असमर्थ रही हैं। साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि दल किन महिलाओं को आगे लाएँगे, क्या वे वास्तव में स्वतंत्र और सशक्त नेत्रियाँ होंगी, या केवल परिवारवाद के विस्तार के रूप में उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। पंचायत स्तर का अनुभव इस संदर्भ में मिश्रित रहा है। एक ओर लाखों महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण प्रशासन में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, पेयजल, स्वच्छता और विद्यालयों के विषय में निर्णय लिए हैं; तो दूसरी ओर अनेक स्थानों पर परिवार के पुरुष सदस्य ही वास्तविक निर्णय-कर्ता बने रहे और महिला प्रतिनिधि केवल प्रतीकात्मक भूमिका तक सीमित रहीं।

इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में स्थान मिलना चाहिए। संसदीय समितियों में, मंत्रिमंडल में, नीति-निर्माण के हर स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आरक्षण द्वार खोलता है, किंतु उस द्वार से होकर जो यात्रा होती है, वह वातावरण, व्यवस्था और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इस आरक्षण के भीतर उनकी पर्याप्त भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, यह प्रश्न अभी विमर्श की प्रतीक्षा में है।

भारत इस समय एक ऐसे ऐतिहासिक सन्धिकाल पर खड़ा है, जहाँ से दो मार्ग जाते हैं। एक मार्ग वह है जहाँ यह सारी व्यवस्था महिला आरक्षण, परिसीमन, सीट-वृद्धि - एक समग्र, संतुलित और संवेदनशील ढंग से लागू होती है और भारतीय लोकतंत्र वास्तव में अधिक समावेशी, अधिक प्रतिनिधिक और अधिक न्यायपूर्ण बनता है। दूसरा मार्ग वह है जहाँ ये प्रावधान केवल कागजी रह जाते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक विभाजन गहरे होते हैं और एक ऐतिहासिक अवसर व्यर्थ चला जाता है।

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक परिपक्वता इसी में प्रकट होगी कि वह इन जटिलताओं के बीच संतुलन साध सके, संघीय भावना की रक्षा करते हुए महिलाओं को वास्तविक सत्ता-भागीदारी दे सके और यह सुनिश्चित कर सके कि प्रतिनिधित्व केवल एक संख्यात्मक उपलब्धि न बनकर सामाजिक परिवर्तन का सेतु बने। यह बहस केवल एक अधिनियम या एक प्रक्रिया की बहस नहीं है - यह उस प्रश्न की बहस है कि भारत किस लोकतंत्र का निर्माण करना चाहता है।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

स्वामी-स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा अनवर ऑफसेट एम- 58, 59 बेसमेंट विकासदीप बिल्डिंग स्टेशन रोड लखनऊ से मुद्रित ई-4 सेक्टर-एम/29 अपोजिट उमान एन्क्लेव अलीगंज लखनऊ 226024 से प्रकाशित संपादक-राजीव कुमार शुक्ला , मो0-9511151254 Mail:

संक्षिप्त खबरें

लोहिया-अंबेडकर विचार गोष्ठी, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के बैसवारा इंटर कॉलेज के गोविंद हॉल में रविवार को डॉ. लोहिया अंबेडकर विचार मंच की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लालबिहारी यादव ने कहा कि अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आज इस अधिकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल उठाने वालों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है, लेकिन वर्तमान समय में संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा कमजोर होती दिखाई दे रही है। लोहिया और अंबेडकर ने जिस समानता के समाज का सपना देखा था, आज उसमें विषमता बढ़ती जा रही है। जाति और धर्म के नाम पर तनाव बढ़ना चिंता का विषय है। लालबिहारी यादव ने कहा कि 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और इसी मार्ग पर चलकर समाज को नई दिशा दी जा सकती है। कार्यक्रम का संचालन संयोजक राजेश चंद्रा ने किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुमित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान लालजी यादव, शैलेंद्र बहादुर यादव, शेखर यादव, अंशु यादव और शिवराम प्रजापति सहित कई लोग उपस्थित रहे।

आरोग्य स्वास्थ्य मेले में मरीजों का इलाज, मुफ्त दवाएं वितरित

स्वतंत्र प्रभात ब्रेकिंग न्यूज़

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल 102 मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं भी वितरित कीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंबारा पश्चिम में 18 मरीजों का उपचार किया गया। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहटा कला में सबसे अधिक 38 मरीज पहुंचे। भैरों मिश्रा केंद्र पर 19 मरीजों का इलाज हुआ, जबकि जगतपुर भिचकौरा स्थित केंद्र पर 27 मरीजों की जांच और उपचार किया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमल पटेल ने बताया कि मेले में आए सभी 102 मरीजों को उचित परामर्श और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं।

हेल्प लाइन नंबरों की जानकारी देकर महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

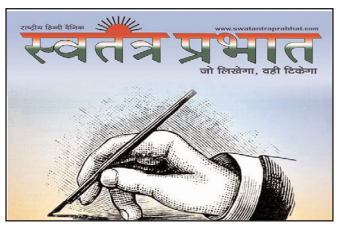

ड्रमंडगंज। ड्रमंडगंज क्षेत्र क्षेत्र के रतेह चौराहा पर रविवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। मिशन शक्ति प्रभारी एसआइ रमेश यादव ने महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 112,1090,1076,1098,1930,108 आदि की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। महिलाओं से कहा कि कोई भी समस्या आने पर इन हेल्प लाइन नंबरों पर फोन कर तत्काल मदद ले सकती हैं।कहा कि आपातकालीन स्थिति में वूमेन पावर लाइन 1090 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करें पुलिस सहायता के लिए पहुंचेगी। महिला कांस्टेबल छाया ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को नजर अंदाज नही करें बल्कि अपने परिजनों और पुलिस को सूचना दें। पुलिस आपकी सहायता करेगी।एसआइ रमेश यादव ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान फेज पांच के तहत महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान महिला कांस्टेबल ज्योति पासवान मौजूद रहीं।

मऊ गांव में हंसवा ड्रेन की पटरी पर खड़े बेशकीमती सरकारी पेड़ों पर वन माफियाओं ने चलाया आरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली: क्षेत्र के मोतीगंज मजरे मऊ गांव में हंसवा ड्रेन की पटरी पर खड़े बेशकीमती सरकारी पेड़ों की अवैध कटान का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ड्रेन खुदाई कार्य की आड़ में सक्रिय वन माफियाओं ने शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात दर्जनों हरे-भरे पेड़ों पर आरा चलाकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। सूचना मिलते ही हरकत में आए वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब 45 कुंतल लकड़ी (मोटा बोटा) बरामद कर कब्जे में ले लिया है, जबकि बड़ी मात्रा में लकड़ी पहले ही खपाई जा चुकी है।

आपको बता दें कि, ग्रामीणों के अनुसार, हंसवा ड्रेन के किनारे वर्षों से खड़े जामुन, नीम, सफेदा और गूलर जैसे कीमती पेड़ों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में पेड़ों को काटकर तेजी से उनकी ढुलाई की गई, ताकि किसी को भनक न लगे। हालांकि सुबह जब पटरी खाली दिखी तो ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। शनिवार को मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच के दौरान 45 कुंतल लकड़ी बरामद की। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, करीब 54 कुंतल लकड़ी अमेठी जनपद के सेमरौता कस्बे में एक व्यापारी को बेचे जाने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। इस घटना ने वन विभाग की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि, इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। वहीं, पर्यावरण प्रेमियों ने इसे क्षेत्र के हरित संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया है।

वन रेंजर नावेद सिद्दीकी ने बताया कि, मामला गंभीर है और विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लकड़ी को कब्जे में ले लिया है। वन माफियाओं की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि, जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल, इस घटना के बाद क्षेत्र में वन माफियाओं की सक्रियता को लेकर दहशत का माहौल है और लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कैंसर पीड़िता की मदद के लिए आगे आ रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता

● मंडल महामंत्री ने रुपया 27485 व लालगंज भाजपा नगर संयोजक डा.बाबू तिवारी ने 10000 देकर किया मदद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली... सतांव चुनाव आते ही विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता विधायक, एमपी, एम.एल.ए.गांव की गलियों में जनता से बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव की गलियों की ओर निकलना भी मुनासिब नहीं समझते क्षेत्र की रहने वाली एक अत्यंत गरीब महिला जो लगभग 6 माह से कैंसर होने के कारण जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है ऐसी स्थिति में कोई भी आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है लेकिन अपनी दरियादिली दिखाते हुए कैंसर पीड़ित महिला कि मदद के लिए आज लालगंज भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री राजेश कुमार व भाजपा नगर संयोजक डॉक्टर बाबू तिवारी ने परिवार से मिलकर हर संभव इलाज तथा आर्थिक मदद का आश्वासन दिया साथ ही आर्थिक मदद के रूप में रुपए 27485 परिवार को इलाज करने के लिए सतांव क्षेत्र के शहजाद पुर गांव की रहने वाली कैंसर पीड़िता गुड्डी प्रजापति पत्नी गुड्डू प्रजापति जो कि लगभग 6 माह से कैंसर से पीड़ित है जिसका कई जगह इलाज कराने के बाद भी स्थिति नाजुक होती चली गई गरीबी के चलते जहां दो वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे परिवार ने इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कैंसर पीडित गुड्डी की माली हालत की जानकारी मिलते ही लालगंज भाजपा के नगर संयोजक व बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर बाबू तिवारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री राजेश कुमार पीड़ित के घर जाकर पूरा हाल जाना और घर वालों तथा कैंसर पीडिता को जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहां की हम हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे वहीं गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे डॉक्टर बाबू तिवारी ने इसके पहले 10000 की मदद करके गरीब पीड़िता का हौसला बढ़ाया था उन्होंने यह भी बताया कि हम अपने संगठन से कहकर आगे और भी सहायता करेंगे जिससे भविष्य में और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया जा सके।

ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र का 20वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया

स्वतंत्र प्रभात ब्रेकिंग न्यूज़

प्रवचन के जरिए दिया राजयोग और सात्विक जीवन का संदेश।

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के महेश नगर स्थित ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र का 20वां वार्षिकोत्सव रविवार को उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर माउंट आबू से आए हितेश भाई ने अपने प्रवचन में राजयोग के चार आधार बताए। उन्होंने कहा कि सात्विक अन्न, सत्संग और ब्रह्मचर्य जीवन को शुद्ध बनाते हैं। इनके बिना परमात्मा से सच्चा संबंध संभव नहीं है। मन की शांति और आत्मबल के लिए इन सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। सेवा केंद्र की संचालिका अलका दीदी ने बताया कि केंद्र की स्थापना 25 मई 2006 को हुई थी। तब से अब तक समाज के विभिन्न वर्गों को ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य गुणों का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बहनों ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां दीं। संस्था की सक्रिय सदस्य अखिलेश ने अतिथियों को संस्था की सेवाओं की जानकारी दी। इस मौके पर पवन सिंह, सुरेश सिंह, सरिता गुप्ता, अनिल गुप्ता, राहुल भदोरिया, हरिनाम सिंह, अवनेन्द्र सिंह और जयप्रकाश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।

घर में घुसकर पिता-पुत्र पर फायरिंग, दोनों गंभीर, गांव में दहशत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद- सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंगेथवा के तुरनी गांव में रविवार तड़के करीब 3 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पिता और उसके मासूम बेटे पर ताबड़तोड़फायरिंग कर दी। इस हमले में 35 वर्षीय सुनील कुमार और उनका तीन वर्षीय पुत्र अभय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल फैल गया। परिजन दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बिजली काटकर दिया वारदात को अंजाम परिजनों के अनुसार हमलावरों ने पहले घर के बाहर लगा बिजली का केबल काट दिया, जिससे पूरे घर में अंधेरा छा गया। इसके बाद बदमाशों ने घर के बाहर ईंटों से बंद किए गए दरवाजे पर लगे तिरपाल को हटाकर अंदर घुसकर सो रहे पिता-पुत्र पर फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज से आसपास के लोग जाग गए, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे।

-लूट की आशंका, मंदिर का ताला भी टूटा मिला जांच के दौरान पुलिस को घर से करीब 100 मीटर दूर एक मंदिर के कमरे का ताला टूटा हुआ मिला,जहां से राशन सहित कुछ सामान गायब पाया गया। ग्रामीणों का मानना है कि वारदात लूट के इरादे से की गई हो सकती है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। परिवार ने जताई हैरानी, नहीं थी किसी से रंजिश पीड़ित के बड़े भाई किशोरी लाल ने बताया कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है।

-पुलिस जांच में जुटी, टीमें गठित प्रभारी निरीक्षक मुकेश वर्मा ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। हमलावरों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और मामले की गहन जांच जारी है। जबकि इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रकरण में छात्रा के आरोप जांच में निकले निराधार

तीन सदस्यीय समिति ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट

महमूदाबाद- सीतापुर बिलौली बाजार स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज से जुड़ा मामला अब पूरी तरह से जांचोपरांत स्पष्ट हो गया है। छात्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के बाद त्रिस्तरीय समिति ने उन्हें निराधार करार दिया है। समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ जिलाधिकारी को सौंप दी है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व विद्यालय की छात्रा शिवानी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे गंभीर अवस्था में सीएचसी महमूदाबाद लाया गया था। इसके बाद छात्रा ने विद्यालय की कुछ शिक्षिकाओं पर झाड़ू-पोंछा कराने, खाना बनवाने, काम न करने पर भूखा रखने और लंबे समय तक खड़ा रखकर प्रताड़ित करने जैसे आरोप लगाए थे। इस मामले में शिक्षिका प्रियंका, अनुराधा और मानसी श्रीवास्तव के नाम भी सामने आए थे, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में एसडीएम बिसवां, एसडीएम महमूदाबाद और बेसिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया था। समिति को 24 घंटे के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे,11 अप्रैल को समिति ने विद्यालय पहुंचकर गहन जांच की। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं और स्टाफ के बयान दर्ज किए गए तथा सीसीटीवी फुटेज का भी बारीकी से परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि छात्राओं को निर्धारित समय के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और उनसे किसी प्रकार का निजी कार्य नहीं कराया जाता है। इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित छात्राओं का आपसी व्यवहार पहले से अनुशासनहीन रहा है, जिस पर विद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व में परामर्श और चेतावनी दी जा चुकी थी, समिति ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट किया कि लगाए गए सभी आरोप असत्य और निराधार हैं। जांच रिपोर्ट साक्ष्यों सहित जिलाधिकारी को सौंप दी गई है, जिसके बाद मामले पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

बिसवां सीतापुर बिसवां नगर में रविवार को सेवा भारती के तत्वाधान में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सेंट जेवियर्स स्कूल, मगरहिया बाजार में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श, दवा वितरण, शुगर जांच एवं ब्लड प्रेशर (बीपी) जांच की सुविधा प्रदान की गई। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश तिवारी एवं डॉ. विमल गुप्ता ने मरीजों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया और नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया। कार्यक्रम में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं में राहुल सिंह पवार, सचिन जी, मोहित जसवाल, आशीष, अंशु रस्तोगी, आनंद एवं नवल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में कुल 40 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिला।

कोतवाली क्षेत्र के ओथी गांव में बलपूर्वक हरे पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद

महराजगंज/रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र के ओथी गांव में बलपूर्वक हरे पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासिनी सुखदेई पत्नी सहवददीन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही राम अवध पुत्र मोहललाल जबरन उसकी जमीन पर लगे पेड़ काटकर रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता के अनुसार, विपक्षी दबंगई के बल पर मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और पेड़ काटना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर जब वह अपने परिजनों व ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची तो आरोपी पक्ष अपने करीब 30 साथियों के साथ वहां से भाग निकला। इस दौरान कुछ पेड़ों को नुकसान भी पहुंचाया गया। सुखदेई का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पहले कोई सहमति नहीं दी थी और विपक्षी मनमाने तरीके से उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में भी आरोपी फिर से आकर पेड़ काट सकते हैं।पीड़िता ने पुलिस से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा उनके पेड़ों व जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बबुरिहा धाम स्थित पावन तपोस्थली में हुआ भव्य विशाल भंडारे का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली: क्षेत्र के प्रसिद्ध आस्था केंद्र बबुरिहा धाम स्थित पावन तपोस्थली पर विराजमान स्वामी हरिदास जी महाराज कुटी के तृतीय महन्त पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा, भक्ति और परंपरागत विधि-विधान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नीलू सिंह के संयोजन में कुटी प्रांगण में विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दूर-दराज के जनपदों सहित प्रदेशभर से आए संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं एवं शिष्यों ने सहभागिता कर प्रसाद ग्रहण किया।

आपको बता दें कि, पुण्यतिथि कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधिवत पूजन-अर्चन से हुई, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं ने दिवंगत महन्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रभु श्रीचरणों में स्थान देने की कामना की। पूरे कुटी परिसर में आध्यात्मिक वातावरण व्याप्त रहा, जहां भक्ति-भाव से ओतप्रोत श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

बबुरिहा धाम स्थित यह सिद्ध कुटी स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम से दूर-दूर तक प्रसिद्ध है और क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था का केंद्र मानी जाती है। कुटी के द्वितीय महन्त बाबा अवसान दास जी महाराज को सिद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता था। मान्यता है कि, वे गहन आध्यात्मिक ज्ञान के धनी थे। संत समाज में जब भी किसी जटिल शास्त्रार्थ का समाधान नहीं निकलता था, तब उन्हें अयोध्या धाम आमंत्रित किया जाता था, जहां वे अपनी विद्वता से कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर संतों को संतुष्ट करते थे।

इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तृतीय गद्दीधारक पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज ने भी कुटी की गरिमा और आध्यात्मिक धारा को सुदृढ़ बनाए रखा। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई थी। उनके ब्रह्मलीन होने के उपरांत यह प्रथम भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय संभ्रांत नागरिकों, श्रद्धालुओं तथा संत-महात्माओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने महन्त जी के सादगीपूर्ण जीवन, आध्यात्मिक साधना और समाज के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूरे आयोजन में सामाजिक, धार्मिक एवं पारंपरिक समन्वय की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

अंडर-18 क्रिकेट टूर्नामेंट: अटौरा टीम का शानदार प्रदर्शन, भूलसी को लगातार तीसरी हार, अजय प्रधान की टीम को करारी शिकस्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। अंडर-18 क्रिकेट टूर्नामेंट में अटौरा टीम ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए भूलसी की अजय प्रधान की टीम को करारी शिकस्त दी। यह मुकाबला शुरुआत से ही रोमांच से भरपूर रहा, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, अटौरा टीम ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ अटौरा ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि भूलसी टीम के खिलाफ अपनी लगातार तीसरी जीत भी दर्ज की, जिससे उनका मनोबल काफी ऊंचा हो गया है।

मैच की शुरुआत में अटौरा टीम के बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। टीम के युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रिंस उर्फ बल्लू (15 वर्ष) ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने मात्र 18 गेंदों में 54 रन ठोककर विरोधी टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी पारी में कई शानदार चौके-छक्के शामिल रहे, जिससे दर्शक झूम उठे और मैच का रुख पूरी तरह अटौरा की ओर मुड़ गया। वही अटौरा टीम को 140 रन बनाने थे,जो कि केवल 9 ओवर में अटौरा की ने लक्ष्य हासिल कर लिया7

प्रिंस के अलावा विनीत कुमार (17 वर्ष) ने भी शानदार सहयोग देते हुए 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने टीम को मजबूत आधार दिया। इसके साथ ही अविनाश, निखिल, अरविंद और अंकुश गौतम ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उपयोगी रन जोड़े, जिससे टीम का कुल स्कोर काफी प्रतिस्पर्धात्मक बन गया। गेंदबाजी में भी अटौरा टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रिंस पासी ने अपनी सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वहीं टीम के कप्तान आजाद ने भी नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर भूलसी टीम के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया।

फील्डिंग में भी अटौरा टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। टोबू ने कई बेहतरीन और मुश्किल कैच पकड़कर मैच का रुख पूरी तरह अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। उनकी फुर्ती और सतर्कता ने विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। वहीं राज ने भी मैदान पर शानदार फील्डिंग करते हुए कई रन बचाए और टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर, भूलसी की अजय प्रधान की टीम इस मैच में पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई। टीम के प्रमुख बल्लेबाज शिवा, अनुज, लक्की और पारस अटौरा के मजबूत

गेंदबाजी आक्रमण के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके और एक के बाद एक विकेट गंवाते चले गए। बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम कभी भी मैच में वापसी नहीं कर पाई।

लगातार तीन बार अटौरा से हार झेलने के बाद भूलसी टीम के सामने अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की चुनौती है। उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में सुधार करने की जरूरत है। वहीं अटौरा टीम की बात करें तो इस जीत ने उन्हें टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया है। टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर है और जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, वह आने वाले मैचों के लिए शुभ संकेत है। अगर अटौरा टीम इसी तरह संतुलित और आक्रामक खेल जारी रखती है, तो टूर्नामेंट का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन सकती है।

जिलाधिकारी डॉ राजा गणपति आर ने पालिका परिषद मिश्रिख व नैमिषारण्य का किया औचक निरीक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने आज नगर पालिका परिषद मिश्रिख व नैमिषारण्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से हैंडपंपों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने हैंडपंपों की मरम्मत से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया तथा यह जानकारी ली कि कितने हैंडपंप वर्तमान में क्रियाशील हैं और कितने खराब पड़े हैं। निरीक्षण के दौरान हैंडपंप अभिलेखों में कमी पाए जाने पर उन्होंने संबंधित कर्मचारी (पटल सहायक) का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

साथ ही जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी से वार्डों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा सफाई, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पानी की टंकी की सफाई से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी (ईओ) पर नाराजगी व्यक्त की तथा कड़े निर्देश दिए कि सभी अभिलेख/फाइलें अद्यतन एवं पूर्ण रूप से संधारित रखी जाएं।

जिलाधिकारी ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड में सभी स्ट्रीट लाइट पोलों का क्रमांक (नंबरिंग) अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि निगरानी एवं अनुरक्षण कार्य सुचारु रूप से हो सके। स्ट्रीट लाइट से संबंधित अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने पटल सहायक का वेतन रोकने के निर्देश दिए तथा अधिशासी अधिकारी को व्यवस्था में सक्रियता एवं रुचि के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्टर का भी अवलोकन किया तथा कुछ आवेदकों से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर सेवाओं की स्थिति के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने ढ्ढत्रक्र क्क्षह्लह्ड्डद्य की समीक्षा की। शिकायतें रजिस्टर में दर्ज न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित पटल सहायक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जनसुनवाई रजिस्टर में शिकायतें दर्ज न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अधिकारी (ईओ) को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का विधिवत पंजीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का भी अवलोकन किया। सेवा पुस्तिकाओं में अवकाश अंकित न पाए जाने पर उन्होंने संबंधित पटल सहायक का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सेवा पुस्तिका के संधारण में रुचि न लेने पर अधिशासी अधिकारी (ईओ) पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों से संबंधित कक्ष में जाकर पत्रावलियों का भी अवलोकन किया। पत्रावलियों में कमी पाए जाने पर संबंधित पटल सहायक का वेतन रोकने के निर्देश दिए तथा अभिलेखों/पत्रावलियों का सुव्यवस्थित

एवं अद्यतन रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने वाहनों के लॉगबुक का भी निरीक्षण किया। लॉगबुक में अधिशासी अधिकारी (ईओ) के हस्ताक्षर न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा ईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वंदन योजना के अंतर्गत नगर मिश्रिख स्टेशन से सीताकुंड धर्मशाला तक बनी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता की जांच की तथा उसकी लंबाई-चौड़ाई का मापन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किए जाएं। इस दौरान अतिरिक्त अधिकारियों ने नगर के विभिन्न वार्डों में जाकर स्थानीय नागरिकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की तथा उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए।

संक्षिप्त खबरें

डॉक्टर दास नही रहे कोयलांचल क्षेत्र में शोक की लहर, छागई

भारी जनसमूह अंतिम यात्रा में हुए सम्मलित

बुढ़ार- कोयलाचंल क्षेत्र बुढ़ार के चर्चित नामी गिनामी दात के डॉक्टर दास जी मृदुभाषी सरल स्वाभाव के धनी रहे, एक वर्ष से गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे, जिनका इलाज हैदराबाद बाम्बे भोपाल में चला, जो दिनांक 11.04.2026 को भोपाल कैंसर अस्पताल में अंतिम सांस ली, आज 12.04.2026 को गृह नगर बुढ़ार में शांतिवन में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में डॉ. दास के परिजनों के साथ ब्लाक कालोनी व बुढ़ार धनपुरी, अमलई शहडोल से सैकड़ों लोगों ने सम्मलित होकर शोक संवेदना दी। जिसमें सुनील दास, बी.पी.तिवारी, कमलेष श्रीवास्तव, अषोक तिवारी, संभू पांडे, संजू चांदवानी, प्रकाष चांदवानी, सच्चू चांदवानी, रवि डोडवानी, एस.के. भट्टा चार्य आभा शुक्ला, पुष्पा तिवारी, अरूणा श्रीवास्वत, मनोज सिंह, अनिल शुक्ला, सूरज सिंह, डॉ. एन.के. अग्रवाल डॉ. जे.एम. गर्ग, डॉ. शेखर, डॉ. मिश्रा, रवि गुप्ता, डॉ. अंजली सरकार, कमलेष गुप्ता, राजू सेठिया, राजकुमार गुप्ता, अरविन्द तिवारी, पवन नियरसेस, अवधेष नामदेव, मनोज चतुर्वेदी, सहित सैकड़ों नम आंखो से श्रंद्धाजली दी एवं मृतक आत्मा की शांति लिए प्रार्थना कर इस कष्ट में दुखी परिवार को सहन शक्ति भगवान दें।

पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

बलिया उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और घोसी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का रविवार दोपहर निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हुआ। उनके निधन की खबर से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। रामगोविन्द चौधरी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हरिनारायण राजभर जमीन से जुड़े और स्पष्टवादी नेता थे, जिनके साथ काम करने का उन्हें अवसर मिला। वहीं, सनातन पाण्डेय ने कहा कि राजभर आम जनमानस की आवाज थे और उन्होंने हमेशा गरीबों व कमजोर वर्गों के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय ने बताया कि स्वर्गीय राजभर कुछ समय तक पार्टी में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। गौरतलब है कि हरिनारायण राजभर ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर घोसी सीट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा वे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार में कारागार मंत्री भी रह चुके थे। बलिया जनपद के बेल्थरारोड विधानसभा क्षेत्र के टमुनिया गांव निवासी हरिनारायण राजभर के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

149 मरीजों की जांच कर दी गई दवाएं

सिद्धार्थनगर/न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्कोहर में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बढ़ते हुए तापमान और बदलते मौसम के कारण स्वस्थ्य मेले में भारी भीड़ रही। सुबह 10बजे से शिविर में दोपहर तीन बजे तक कुल 93 मरीजों का पंजीकरण कर उनकी जांच की गई और निःशुल्क दवाएं दी गई। मेले में आयुष संविदा चिकित्सक डा. एस. सी. शर्मा ने मरीजों का उचित चिकित्सीय परामर्श दिया। खान पान में सादा खाना खाने को सलाह दी।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ोरा कठौतिया रामनाथ में जन आरोग्य मेले में मरीजों की कुल संख्या 56 जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े, महिला मरीज शामिल रही, बच्चों में ज्यादातर उलटी दस्त के मरीज रहे। डाक्टर राहुल कुमार ने चेक कर दवा दी। इस मौके पर फार्मासिस्ट त्रिशुल चतुर्वेदी, धीरज राय, राजू, मनोज आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

हिजबुल्लाह के बहाने पूरे गांव तबाह? इजराइल की कार्रवाई पर मानव अधिकार संगठनों ने उठाए गंभीर सवाल

● इजरायल द्वारा दक्षिण लेबनान में अपनाई जा रही 'डोमिसाइड' की रणनीति ने एक नई मानवीय और कानूनी बहस छेड़ दी है, जहां नागरिक घरों का विनाश सैन्य आवश्यकता से कहीं अधिक बताया जा रहा है।

इस कार्रवाई का उद्देश्य हिज्बुल्लाह को निशाना बनाने के साथ-साथ एक बफर जोन स्थापित करना है, जिसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दक्षिण लेबनान से आ रही तस्वीरें एक बार फिर युद्ध की भयावहता को सामने ला रही हैं, जहां पूरे के पूरे गांव मलबे में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और मानवाधिकार संगठनों ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। मौजूद जानकारी के अनुसार, इजरायली सेना ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में कई गांवों को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया है। सामने आए वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों में तैयबेह, नकौरा और देइर सेरयान जैसे गांवों में बड़े पैमाने पर धमाकों के जरिए घरों को पूरी तरह नष्ट करते देखा गया। हालांकि कुछ दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

बता दें कि यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सीमा के पास मौजूद गांवों में सभी घरों को खत्म करने की बात कही थी। गौरतलब है कि इससे पहले गाजा पट्टी के रफाह और बीत हनून जैसे इलाकों में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई गई थी, जहां बड़ी संख्या में घर तबाह हुए थे। विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस तरह की रणनीति को 'डोमिसाइड' कहा जाता है, जिसमें जानबूझकर नागरिक इलाकों को इस तरह नष्ट किया जाता है कि वे रहने लायक न रहें। उनका मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में गंभीर सवाल खड़े करता है।

इजरायल की ओर से कहा गया है कि इन कार्रवाइयों का मकसद हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना है, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे आम नागरिकों के घरों और ढांचों के बीच छिपे हुए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पूरे गांवों को नष्ट करना किसी भी सैन्य जरूरत से कहीं ज्यादा है। गौरतलब है कि इजरायल दक्षिण लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है, जो लितानी नदी तक फैला हो सकता है। इस योजना के तहत विस्थापित लोगों को तब तक अपने घरों में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक उत्तरी इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती।

वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के खत्म हो जाने जैसा है। तैयबेह के एक दुकानदार ने बताया कि उनका कारोबार, यादें और पूरा जीवन एक ही पल में खत्म हो गया। कई लोगों ने खुद को अब बेघर और शरणार्थी जैसा महसूस करने की बात कही है। जानकार मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ मौजूदा संघर्ष तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक असर छोड़ती हैं। दक्षिण लेबनान के कई परिवार पहले से ही दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं और अब उनके लिए अपने घर लौटने की उम्मीद और भी कमजोर हो गई है।

पश्चिम एशिया में शांति के लिए पुतिन की नई चाल, ईरान के सामने रखी मध्यस्थता की पेशकश

● रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम एशिया में राजनीतिक-कूटनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। यह पहल रूस की वैश्विक भूमिका को दर्शाती है, भले ही वह खुद यूक्रेन संघर्ष में उलझा हुआ हो।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक नया कूटनीतिक पहलू सामने आया है, जहां रूस ने शांति बहाली में भूमिका निभाने की पेशकश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत के दौरान मध्यस्थता की इच्छा जताई है। मौजूद जानकारी के अनुसार, क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान खोजने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस इस दिशा में हर संभव सहयोग देने और स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बता दें कि यह पेशकश ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुई सीधी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से उम्मीद थी कि युद्धविराम को स्थायी रूप दिया जा सकेगा, लेकिन मतभेद बरकरार रहने से स्थिति फिर अनिश्चित हो गई है।

अमेरिका की ओर से कहा गया कि बातचीत इसलिए विफल रही क्योंकि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी स्थिति में बदलाव नहीं किया। वहीं ईरान ने इसके उलट अमेरिका पर ही बातचीत बिगाड़ने का आरोप लगाया है, हालांकि उसने विस्तार से कारण नहीं बताए हैं। गौरतलब है कि रूस पहले भी इस तरह की मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। साल 2025 में भी जब क्षेत्र में संघर्ष तेज था, तब पुतिन ने कहा था कि ईरान के परमाणु मुद्दे का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए होना चाहिए।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रूस खुद यूक्रेन के साथ लंबे समय से संघर्ष में उलझा हुआ है और वहां भी शांति प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसके बावजूद रूस का यह कदम वैश्विक कूटनीति में उसकी सक्रिय भूमिका को दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस की मध्यस्थता स्वीकार की जाती है तो यह क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक अहम पहल हो सकती है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी होगी।

गाँव चलो अभियान के तहत भाजपाइयों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

सिद्धार्थनगर/भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के अंतर्गत रविवार को नगर पंचायत कपिलवस्तु क्षेत्र अंतर्गत बभनी एवं अन्य बूथों पर भाजपा नेता नामित सभासद नितेश पाण्डेय ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ घर - घर जनसंपर्क कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए पत्रक वितरित किया इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में जनता से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनके लाभों से अवगत कराया। और बताया कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मुन्नी देवी, शक्ति केंद्र संयोजक रणजीत चौधरी बूथ अध्यक्ष/सभासद वीरू कन्नौजिया सहित राधेश्याम संतोष कुमार, सूरज चौधरी, शिवपूजन, अजय कुमार अरुण कुमार आदि रहे।

प्रीत विहार में क्लब के बाहर फिर फायरिंग, स्कूटी सवार युवकों ने चलाई गोलियां; लोगों में दहशत

पूर्वी दिल्ली। प्रीत विहार इलाके में क्लबों के बाहर फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक सप्ताह पहले शोशा क्लब के बाहर हुई फायरिंग की घटना में शामिल बदमाशों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकी है, वहीं अब बिग बैंग क्लब के बाहर स्कूटी सवार दो युवकों ने शनिवार देर रात फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं और उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी विवेक कुमार ने बताया कि देर रात करीब दो बजे वह घर पर थे तभी गोली चलने की आवाज आई। दो युवक स्कूटी पर सवार होकर क्लब के बाहर पहुंचे थे। उन्होंने फायरिंग की और फरार हो गए। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। फायरिंग के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर पुलिस को जानकारी दी गई, हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी घटना की जानकारी से इनकार किया है।

लोग बोले, स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से चल रहे क्लब

एक सप्ताह पहले भी प्रीत विहार स्थित शोशा क्लब के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली लगी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में कई क्लब नियमों को ताक पर रखकर और बिना लाइसेंस के देर रात तक संचालित हो रहे हैं। बिग बैंग क्लब भी देर रात तक खुला रहता है।

जयकांत मिश्रा सदस्य पद के लिए हाई कोर्ट में फार्म भरते समय की शक्ति प्रदर्शन

सैकड़ो वाहन हजारों अधिवक्ताओं ने जुलूस में हुए शामिल जीत दिलाने का किया वादा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बुढार अधिवक्ता संघ बुढ़ार के अध्यक्ष जयकांत मिश्रा मध्यप्रदेष राज अधिवक्ता परिषद के वर्ष 2026 12 मई को हो रहे चुनाव को लेकर प्रदेष भर में सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जबलपुर हाई कोर्ट परिसर में विषेष हलचल देखने को मिली जब जाने माने अधिवक्ता बुढ़ार संघ के अध्यक्ष जयकांत मिश्रा ने सदस्य पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल के दोरान उनके साथ इतिहासिक समर्थक बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे इस तरह का शक्ति प्रदर्षन जबलपुर हाई कोर्ट में देखने को नही मिला था।

सुबह से ही जबलपुर हाई कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का लगा जमावाड़ा जयकांत मिश्रा की जीत तय

सदस्य का फार्म भरते समय जयकांत मिश्रा अपने समर्थको के साथ संगठित एवं तरीके से भारी जन समूह से पहुचे उनके साथ लाव लष्कर कई वरिष्ठ एवं युवा अधिवक्ता भी मौजूद रहे चार पहिया वाहनों के साथ हाई कोर्ट पहुंचे जिससे परिसर के आसपास चुनावी महौल स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगा कि जयकांत मिश्रा की जीत लगभग तय। भारी अधिवक्ता जन समूह में शहडोल अनूपपुर उमरिया, डिंडौरी, मण्डला शहपुरा, सतना रीवा, उचेहरा मैहर कटनी व अन्य कई जिलों अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समर्थकों का कहना था, जयकांत मिश्रा लम्बे समय से अधिवक्ताओं के हितो के लिए सक्रिय रहते और उनके साथ उनकी समस्याओं का समझने का प्रयास करते है, इसलिए वे इस चुनाव एक बहुत के रूप में सामने आ चुके हैं।

जयकांत मिश्रा ने 12 मई को मतदान के लिए सभी अधिवक्ताओं से समर्थन की की अपील

अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अगामी 12 मई 2026 को होने वाले मतदान में बढ़चढ़कर हिस्सा ले और अपने प्रथम वरीयता मत से समर्थन देने का आग्रह किया, उन्होने कहा कि यदि उन्हे जीत का अवसर मिलता है तो वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरे निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करेगे, जयकांत मिश्रा ने यह भी कहा कि अधिवक्ता समाज की एकजुटका ही उनकी समसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत के बल पर परिषद में सकरात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सभी से सहयोग और आर्षीवाद की कामना जताई जबलपुर हाई कोर्ट में आज हुए इस नामांकन ने चुनावी महौल की पूरी तरह इतना गरमा दिया कि आने दिनों में चुनावी गतिविधियों में हर अधिवक्ताओं की आवाज जयकांत मिश्रा को जीताने एवं मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया है, जो म.प्र. हाई कोर्ट राज अधिवक्ता परिषद का चुनाव जयकांत मिश्रा को जीतना तय है।

प्रेमिका के लिए वीरू बना आशिक... टावर पर चढ़ा

● बोला- वह प्रेमिका से शादी करेगा तभी नीचे उतरूंगा- घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के ग्राम कठमोरवा में सिरफिरा आशिक टावर पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका का नाम लेकर उसे बुलाने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर खेसरहा थाना की पुलिस भी पहुंच गई। खेसरहा थाना क्षेत्र के ग्राम कठमोरवा में रविवार की सुबह हड़कंप मच गया, जब एक युवक प्रेम प्रपंच में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान आकाश पुत्र रामवृक्ष जमुवार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह सुबह करीब 9.00से 5. 40 बजे के बीच टावर पर चढ़ा और ऊपर से आवाज देकर अपनी प्रेमिका को बुलाने और उसे शादी करने की मांग कर रहा था। खेसरहा थाना क्षेत्र के कठमोरवा में सुबह एक युवक टॉवर पर चढ़ गया। वह टॉवर की सबसे टॉप वाले प्वाइंट पर पहुंच कर अपनी प्रेमिका को बुलाने और उससे शादी करने की जिद करने लगा।

सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची

प्रभारी निरीक्षक अनुप कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ पहुंचे, और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर एकत्र हो गए। काफी समझाने-बुझाने के बाद भी युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ है। वह लगातार अपनी प्रेमिका को बुला रहा था। प्रशासन लगातार बातचीत कर स्थिति पर काबू पाया और युवक को टावर से नीचे उतरवाया। पुलिस ने युवक को सुरक्षित हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, विभाग ने इन पदों पर निकाली भर्ती

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने रिसर्च असिस्टेंट सहित कुल तीन पदों पर भर्ती निकाली है। डीयू ने जिन तीन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर एप्लीकेशन मांगे हैं, उनमें रिसर्च असिस्टेंट के तीन और फील्ड इनविजिलेटर का एक पद शामिल हैं। वहीं, जारी पदों के लिए आनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फार्म भरने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फार्म जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित विषय में या किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पीएचडी/एमफिल/पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता, कौशल और तय सालों का अनुभव होना भी अनिवार्य है।

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे जमीन हड़पने के कई मामले गोला तहसील में बने चर्चा का विषय

● शाहजहांपुर- खीरी कनेक्शन अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
संवाददाताः नित्यानंद बाजपेई

लखीमपुर खीरी गोला तहसील क्षेत्र में जमीन हड़पने के चौंकाने वाले कई मामले सामने आए हैं। यह मामले क्षेत्र में चर्चा का विषय तो बने ही है साथ ही साथ, राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों सहित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की भूमिका पर सबाल खड़े करने को काफी है। गोला तहसील में फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र और फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल के जरिए लोगों की जमीन हड़पने के मामलों की आयी बाढ़ ने सूबे के मुखिया के भ्रस्टाचार मुक्त दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर वरासत दर्ज कराने का पहला मामला परगना कुकुरा तहसील गोला के ग्राम हर दुआ का बताया जाता है वैसे आज हम जिन मामलों को आपके सामने उजागर कर रहे हैं वह सभी परगना कुकुरा के ग्राम हर दुआ और खंजनपुर के गंभीर मामले बताये जाते हैं।आरोप लगाया गया है किय हस भी खेल पंचायत सचिव प्रधान और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत का परिणाम है। जिसमें पहला मामला हरिराम पुत्र निवासी ग्राम हर दुआ हाल पता ग्राम घुसनाखोर जिला बस्ती का है पूरा मामला दो जिलों–बस्ती और लखीमपुर खीरी–से जुड़ा बताया जा रहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम हर दुआ निवासी महिला पिंकी देवी पत्नी बिंदर पाल मौर्या पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हरीराम के नाम से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और परिवाररजिस्टरकेसाथ छेड़छाड़ कर फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल भीतैयार करा ली। इसके बाद इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर संबंधित भूमि गाटा संख्या की वारासत अपने पक्ष में दर्ज करा ली गई।

सूत्रों की मानें तो पहले हरीराम को मृतक दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया गया और फिर परिवार रजिस्टर में हेर-फेर कर परिवार रजिस्टर की नकल जारी कराकर मौर्या बिरादरी की पिंकी देवी अनुसूचित जाति के हरीराम की पुत्री बनकर फर्जी वरासत अपने नाम करवा ली।इस खेल में तत्कालीन लेखपाल भूपेंद्र वर्मा का अहम रोल बताया जाता है। वहीं तहसील दार की भी भूमिका सवालों के घेरे में हैं दूसरा मामला तहसील गोला के ग्राम खंजनपुर परगना कुकुरा का है जहां पहले रामू मुकेश ने अपने पिता की मृत्यु प्रमाणपत्र पर पिता और चाचा की जमीन हड़प ली उसके बाद राजस्व विभाग के जिम्मेदारों की मिलीभगत से मुकेश पुत्र रोशन बनकर राम रतन पुत्र रोशन की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने का प्रयास कर रहे हैं।यहां पर भी प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी का खेल सामने आया है।प्रधान और पंचायत सचिव ने विपक्षी गणों से भारी भरकम नजराना लेकर सारे साक्ष्यों को दरकिनार करके मुकेश पुत्र घूरई को मुकेश पुत्र रोशन बना दिया गया। तीसरा सबसे अहम और गंभीर है जहां मृतक शिलाबती पत्नी बालक राम को जिंदा दिखा कर उनकी जमीन की वरासत बालक राम की दूसरी पत्नी जुगरता को फर्जी दस्तावेज के आधार पर शीलावती बना दिया गया।जबकि शीलावती की मृत्यु काफी पहले हुयी थी उसके बाद जुगरता का बालक राम के साथ हुआ था धरौना । यहां पर भी प्रधान पंचायत सचिव और राजस्व विभाग के चर्चित चेहरे लेखपाल भूपेंद्र वर्मा और कानूनगो साहिब ने वगैर किसी जांच पड़ताल के जायज वारिस मृतक सोनू की पुत्री को किनारे कर धनबल की दम पर

तथाकथित /छदमवेश शीलावती के नाम नियम कानून को ताक पर रखकर वरासत भरकर भ्रस्टाचार की बानगी पेश कर दी। हद तो तब हो गई जब मामला न्यायालय नायब तहसील दार के यहां पहुंचा ।यहां पर भी पैसा पहाड़ चढ़ाता है कि कहावत चरितार्थ होती दिखाई दी। सूत्र बताते हैं कि शीलावती और बालक राम से एक लड़के का जन्म हुआ था इसके जन्म के समय ही शीलावती की मृत्यु हो गयी थी उक्त बच्चे का पालन-पोषण उसकी नानी ने किया था। शीलावती भी अपने पिता की इकलौती संतान थी। शीलावती के पति की मृत्यु के बाद उनके नाम जमीन शीलावती की माँ और सोनू की नानी के नाम आ गई थी। सोनू अपनी नानी के पास ही रहता था और उसकी शादी भी उसकी नानी ने ही की थी।सोनू और उसकी पत्नी लक्ष्मी के संसर्ग से एक पुत्री है जो अपने पिता की सम्पत्ति की इकलौती वारिस हैं बीमारी के चलते सोनू की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सोनू की नानी की मृत्यु हो जाती हैं।और फिर शुरू होता है फर्जीवाड़ा और भ्रस्टाचार का गंदा खेल।जमीन जायदाद हड़पने का सुनियोजित प्लान का आगाज लेखपाल, कानूनगो और ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव इस खेल के नायक बनते है और काफी समय पहले मृतक हो चुकी शीलावती को काग़ज़ों पर जिंदा दिखा कर लेखपाल भूपेंद्र और कानूनगो की मिलीभगत से तथाकथित छदमवेश धारी जगराता को शीलावती बनाकर उक्त जमीन की इकलौती वारिस सोनू की नाबालिग लड़की को उसके हक और अधिकार से वंचित करते हुए फर्जी शीलावती बनी जगराता के वरासत आदेश पारित कर दिया गया। इन फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते हुए राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से हेरफेर कर जमीन पर अधिकार स्थापित कर लिया गया।उक्त मामले में नायाब तहसील दार ने स्थलीय निरीक्षण किए बिना ही महा भ्रष्ट लेखपाल की रिपोर्ट पर आदेश पारित कर दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे है।नियमानुसार नाना नानी की जमीन पर उसके नाती या फिर नाती के वारिस का अधिकार होता है ना कि सौतेली माँ का अधिकार होता है। लकिन साहिब तहसील गोला में घटित होने वाले अजब ग़ज़ब खेल भ्रस्टाचार की पोल खोल रहे हैं।गोला उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तहसील है जहां पर भूत जमीन का बयनामा करते देखे जा सकते है।जिसका जीता जागता उदाहरण है कि ग्राम हर दुआ निवासी राम दुलारे पुत्र श्रीराम हाल पता जिला बस्ती की मृत्यु वर्ष 2006 में हो जाती है लकिन वह गोला तहसील में अपनी जमीन की बिक्री करने स्वर्ग से 2023 में पूनःभूत बनकर तहसील गोला आता है और अपनी जमीन की रजिस्ट्री लालजी प्रसाद पुत्र दीन दयाल के नाम कर जाता है इतना ही नहीं मृतक राम दुलारे प्रतिफल भी प्राप्त कर लेता है।

मामले में ग्राम स्तर के अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है, जिससे पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है। फिलहाल, मामलो की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है।

सिपाही से समीक्षा अधिकारी बने यदुनंदन सिंह , प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर तहसील के विकास खंड पहला अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव निवासी यदुनंदन सिंह यादव ने समीक्षा अधिकारी (RO) के पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय सफलता से पूरे इलाके में हर्ष और गर्व का माहौल है। बताया जाता है कि यदुनंदन सिंह वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी (सिपाही) के पद पर भर्ती हुए थे और वर्तमान में अयोध्या पुलिस लाइन में तैनात हैं। नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने यह सफलता हासिल की, जो युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है।

शैक्षिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा महमूदाबाद स्थित सेठ रामगुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज से प्राप्त की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू पॉलिटेक्निक, महमूदाबाद से सिविल ट्रेड में डिप्लोमा किया। उनके पिता स्वर्गीय रामेंद्र सिंह सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के पद पर कार्यरत थे, जिनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। उनकी माता महेशा देवी गृहिणी हैं। परिवार में बहन अंबेश्वरी, भाई दुर्गेश कुमार एनसीसी ऑफिसर, युगराज सिंह (लेखपाल की तैयारी में) तथा ललित कुमार सिंचाई विभाग, सिधौली में क्लर्क हैं।

समीक्षा अधिकारी बनने के बाद 12 अप्रैल 2026 को जब यदुनंदन सिंह अपने पैतृक गांव नया गांव पहुंचे, तो क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भंडिया चौराहा, कुंवर गड्डी चौराहा और नया गांव चौराहा सहित कई स्थानों पर लोगों ने फूल-

मालाओं और मिठाइयों के साथ उनका अभिनंदन किया। बेहमा स्थित सहयोग छात्र शिक्षा समिति कार्यालय में संस्था प्रमुख धर्मेंद्र कुमार पासवान द्वारा उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं, रामपुर भुजंग रोड स्थित यादव मेडिकल स्टोर पर समाजसेवी रंजीत यादव ने उनका अनोखे अंदाज में स्वागत करते हुए लड्डुओं से तौलकर सम्मानित किया, जो पूरे कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा।

इस अवसर पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित रहे और यदुनंदन सिंह को शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में ब्लॉक प्रमुख पहला रावेंद्र यादव उर्फ अजय यादव, प्रतिनिधि उपेंद्र यादव, शिवेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी एवं समाजसेवी रंजीत यादव,अनुज यादव प्रधान सदरावां, विनोद यादव, श्रवण वर्मा, ए के विश्वकर्मा, मनोज पासवान, धर्मेंद्र सिंह पासवान, मंजीत यादव, बबलू गुप्ता, पंकज सोनी, रितेश सोनी, आशीष कुमार, अरुण कुमार, सत्येंद्र सिंह, रंजीत यादव सहित अनेक लोग शामिल रहे। यदुनंदन सिंह यादव की यह सफलता यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण और मेहनत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बनकर उभरी है।